संपादकीय

रेलवे में सुरक्षा हो प्राथमिकता

देश का राजनीतिक परिदृश्य आम चुनाव के रंग में रंगता नजर आ रहा है। लगातार नई योजनाओं के शिलान्यास, घोषणाएं और उद्घाटन उसकी बानगी है। निस्संदेह, विकास में तेजी देश की जरूरतों और रोजगार के लिये अपरिहार्य है। सोमवार को प्रधानमंत्री द्वारा दो हजार रेलवे ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास सुखद ही कहा जाना चाहिए। उन्होंने देश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इकतालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की करीब दो हजार परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 'प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास भी शामिल था। देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन स्टेशनों पर करीब उन्नीस हजार करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जाना है। निस्संदेह, देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों तथा स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता के चलते यह आवश्यक हो गया है कि रेलवे स्टेशनों को सुविधाजनक बनाया जाए। इसमे दो राय नहीं कि रेल विभाग की खस्ता हालत के लिये सस्ती राजनीति भी जिम्मेदार रही है,जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया है। विगत में देखा गया कि गठबंधन सरकारों के दौर में रेल मंत्री का पद हासिल करने के लिए दबाव की राजनीति की जाती थी। जिसका मकसद नेताओं का अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए विशेष ट्रेन चलाना और अपने इलाके के अपने समर्थक बेरोजगारों को नियम-कानून ताक पर रखकर रेलवे में भर्ती करना होता था। यह एक हकीकत है कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में शुमार होने के बावजूद न तो रेल सेवा की गुणवत्ता बन पायी और न ही आर्थिक रूप से रेलवे मजबूत बन पाया। नि:संदेह, आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर रेल के किराये काफी कम हैं। जब भी गुणवत्ता को बनाये रखने के मकसद से रेल के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव आता था तो राजनेताओं द्वारा उसे चुनावी मुद्दा बना लिया जाता था। निस्संदेह, गुणवत्ता की रेल सेवा बनाने के लिये यात्रियों के योगदान की भी जरूरत है।

बहरहाल, इसके बावजूद आज देश में सामान्य रेल यात्रा को पूरी तरह सुविधाजनक व सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। आये दिन रेल दुर्घटनाएं और मानवीय चूक की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में खबर आई थी कि गत पच्चीस फरवरी को जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के चल पड़ी थी। यह ट्रेन बिना ड्राइवर व गार्ड के साठ किलोमीटर की रफ्तार से चल पड़ी थी। इसे तब रोका जा सका जब यह करीब डेढ़ घंटे का सफर तय करके एक छोटे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। गनीमत यह रही कि इसके रास्ते में कोई दूसरी ट्रेन नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया। बताते हैं कि कठुआ स्टेशन पर ड्राइवर व गार्ड को बदला जाना था, लेकिन ड्यूटी खत्म कर रहा ड्राइवर मालगाड़ी में हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। यद्यपि इस आपराधिक लापरवाही के चलते स्टेशन मास्टर समेत छह अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोताही न बरती जाए। निस्संदेह, यह घटना बताती है कि रेलवे की कार्यशैली में बदलाव की आवश्यकता है वहीं चालक और स्टाफ को अधिक सतर्क व जवाबदेह बनाने की जरूरत है। निस्संदेह, रेलवे के ढांचे का विस्तार व आधुनिकीकरण समय की मांग है, लेकिन पहले पुराने रेलवे के ढांचे को सुरक्षित व फुलप्रूफ बनाने की जरूरत है। वहीं रेलवे की पटरियों के रखरखाव के साथ ही रेलवे स्टाफ को इसके परिचालन में अतिरिक्त सावधानी की दरकार है। नि:संदेह, रेल परिचालन में एक छोटी चूक सैकड़ों लोगों के जीवन पर संकट उत्पन्न कर सकती है।

विपक्ष जनभावना को समझने में विफल

दृष्टिकोण

-विकास सक्सेना

सबसे ज्यादा हैरान करने वाला चुनाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। यहां से एक राज्यसभा सदस्य का चुनाव किया जाना था। यहां 68 में से 40 विधायक कांग्रेस के, 25 भाजपा और तीन निर्दलीय हैं। सामान्य तौर पर राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक राज्य में सत्ताधारी दल के साथ खड़े होते रहे हैं इसके अलावा विपक्षी दलों के विधायक भी उसी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं।

राज्यसभा चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग के दम पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में दो अतिरिक्त सीट पर विजय हासिल कर ली। नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी करके क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर हमेशा की तरह बिक जाने या डर जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन इस बार की क्रॉस वोटिंग सिर्फ इतने तक सीमित दिखाई नहीं देती। भाजपा और मोदी विरोधी विपक्षी दलों के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से जनभावना के विपरीत फैसले लिए हैं उनसे इन दलों में तेजी से असंतोष बढ़ा है। खासतौर से अयोध्या में श्रीराम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विपक्षी दलों ने जिस तरह बहिष्कार किया, वह पार्टी के समर्थकों और तमाम नेताओं को रास नहीं आया। तमाम विपक्षी नेता प्रभु राम, सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए था जिससे कई नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए तो कुछ असंतोष की आग को मन में दबा कर बैठे रहे। और अब राज्यसभा चुनाव के मौके पर वे खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई अनोखी बात नहीं है। आज तक राज्यसभा का शायद ही कोई चुनाव हुआ हो जिसमें विधायकों ने अपनी पार्टी के नेतृत्व की अनदेखी करके किसी अन्य दल के उम्मीदवार की मदद न की हो। यह मदद परिस्थितियों के आधार पर तीन प्रकार से की जाती है एक तो विधायक अपना मत सीधे तौर पर विरोधी दल के उम्मीदवार को दे देते हैं, दूसरे वे मतदान में भाग ही नहीं लेते और तीसरे तरीके में वोट तो डालते हैं लेकिन इस तरह कि उनका वोट खारिज हो जाए। तीसरा ज्यादा सुरक्षित तरीका है क्योंकि इसे विधायक की गलती मानकर अनदेखा किया जा सकता है। हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनाव में भी माना जा रहा था कि विधायक पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करेंगे लेकिन इस इस स्थिति से निपटने के लिए विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कोई खास रणनीति तैयार नहीं की।

उत्तर प्रदेश से दस राज्यसभा सदस्यों को चुनकर राज्यसभा जाना था। इसके लिए भाजपा के पास सात तो समाजवादी पार्टी के पास तीन उम्मीदवारों को जिताने के लिए लिए पर्याप्त संख्या बल था। लेकिन भाजपा ने आठवें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतार कर यहां का मुकाबला रोचक बना दिया। दरअसल संजय सेठ पुराने समाजवादी नेता रहे हैं। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव से उनके नजदीकी रिश्ते जगजाहिर थे। समाजवादी पार्टी की नीति निर्धारण में भी संजय सेठ का प्रभावशाली दखल रहता था। संजय सेठ ने 2019 में सपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। ऐसे में जब भाजपा ने आठवें उम्मीदवार के तौर पर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा अखिलेश यादव को तभी ज्यादा सतर्क होकर अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए थी। मतदान से एक दिन पहले सपा मुखिया के रात्रिभोज से नदारद रहकर आठ विधायकों ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। इनमें से छह विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला जबकि अमेठी की विधायक महाराजी प्रजापति ने मतदान से दूर रहकर भाजपा उम्मीदवार की मदद की। गलत तरीके से वोट डालने के कारण बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम अंसारी का वोट अमान्य कर दिया गया।

सबसे ज्यादा हैरान करने वाला चुनाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। यहां से एक राज्यसभा सदस्य का चुनाव किया जाना था। यहां 68 में से 40 विधायक कांग्रेस के, 25 भाजपा और तीन निर्दलीय हैं। सामान्य तौर पर राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक राज्य में सत्ताधारी दल के साथ खड़े होते रहे हैं इसके अलावा विपक्षी दलों के विधायक भी उसी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि यहां का मुकाबला कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। लेकिन भाजपा ने यहां से पूर्व कांग्रेसी हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाकर और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की राह मुश्किल कर दी। यूं तो सिंघवी की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही उनको बाहरी बताते हुए हिमाचल प्रदेश से विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए थे लेकिन उनकी असल मुश्किलें हर्ष महाजन के चुनाव मैदान में उतरने से खड़ी हुईं।

दरअसल हर्ष महाजन का कांग्रेस से चार दशक से भी पुराना रिश्ता था। वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुख्य रणनीतिकार माने जाते थे। वह विधायक, मंत्री और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। उन्होंने 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली थी। भाजपा की ओर से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा होते ही उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन विधायकों की संख्या में भारी अंतर होने की वजह से उनकी जीत की संभावना कम दिखाई दे रही थी। कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधायकों के अपहरण का हरियाणा पर आरोप मढ़ रहे थे। किसी राज्य की पुलिस और खुफिया तंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। अगर इस घटना का किसी आतंकवादी समूह ने अंजाम दिया होता तो क्या यह घटना इतनी ही सामान्य तौर पर ली जाती।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग सिर्फ भाजपा के पक्ष में ही नहीं हुई, भाजपा के खिलाफ भी उसके समर्थक विधायकों ने विरोधी दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा के एक विधायक ने सपा उम्मीदवार को वोट दिया। इसी तरह कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस भाजपा विधायक से अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब रही। भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने वाले विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे बिक गए या फिर केंद्रीय जांच संस्थाओं के डर की वजह से उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। बीते कुछ समय से भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ जिस तरह विष वमन किया है, उसका क्रॉस वोटिंग करने वाले अधिकांश नेताओं ने प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर उसका विरोध किया था। सपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य प्रभु राम, रामचरित मानस और हिन्दू धर्म के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे। तो उदयनिधि स्टालिन जैसे तमाम नेता सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ जहर उगल रहे थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर इन दलों के शीर्ष नेतृत्व ने जनभावना की उपेक्षा की सारी सीमाएं पार कर दीं।

सपा मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक विक्षिप्त तक कह दिया था। अखिलेश यादव के फैसले के खिलाफ सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर विधायकों को रामलला के दर्शन कराने का आग्रह किया था।

सामाजिक समरसता और नारी भावना के उच्चतम सम्मान का अद्भुत प्रसंग

रमेश शर्मा

शबरी जयंती पर विशेष

भक्त शिरोमणि शबरी वनवासी भील समाज से थीं। फिर भी मातंग ऋषि के गुरु आश्रम की उत्तराधिकारी बनी। रामजी ने उनके जूठे बेर खाये। यह कथा भारतीय समाज की उस आदर्श परंपरा का उदाहरण है कि व्यक्ति को पद, स्थान और सम्मान उसके गुण और योग्यता से मिलता है जन्म या जाति से नहीं।

भक्त शिरोमणि शबरी का जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी को हुआ था। इस वर्ष यह तिथि दो मार्च को है। उनका जन्म त्रेतायुग अर्थात रामायण काल में हुआ था। यह कथा बाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरित मानस के अरण्य काण्ड में है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण सहित कुछ अन्य ग्रंथों में है। इसलिये माता शबरी की कथा के यथार्थ पर संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। यह कथानक केवल किसी घटना या रामायण काल के पात्र का विवरण भर नहीं है। यह प्रसंग सफलता प्राप्त करने के लिये समर्पण और एकाग्रता का संदेश देता है।

शबरी कथा में भारतीय समाज जीवन की व्यवस्था का यह दर्शन भी मिलता है कि भारतीय समाज जीवन में किसी को सम्मान या स्थान जन्म और जाति के आधार पर नहीं मिलता अपितु उसके लिये गुण, कर्म और योग्यता आवश्यक है। योग्यता के आधार पर ही देवि शबरी ऋषि आश्रम की प्रमुख बनीं। उनका जन्म वनवासी भील समाज में हुआ था। जीवन की कुछ घटनाओं से उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति का भाव जागा और योग्य गुरु की खोज में निकल पड़ीं। गुरु की खोज करते-करते वे मातंग ऋषि के आश्रम पहुँची। उन्हें आश्रम के भीतर जाने में संकोच हुआ तो उन्होंने आश्रम से बाहर रहकर ही गुरु सेवा का संकल्प लिया। वे उस मार्ग की सफाई करने लगीं जिस मार्ग से ऋषि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिये जाते थे। इसके साथ वे जंगल से लकड़ियाँ लाकर आश्रम में पहुंचाने लगीं। मातंग ऋषि को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि कौन से जो यह सेवा कर रहा है। शिष्यों ने खोजा और देवि शबरी को ऋषि के सामने लाये। प्रसन्न होकर मातंग ऋषि ने देवी शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। देवी शबरी ने अपना जीवन गुरु सेवा में अर्पित कर दिया। ऋषि सेवा करतीं और उनके प्रवचन सुनकर प्रभु भक्ति में लीन हो जातीं। उनकी लगन और समर्पित सेवा ने उन्हें पूरे आश्रम में विशिष्ठ बना दिया। महर्षि मातंग इतने प्रभावित हुये कि वे जब अपना शरीर त्यागने लगे तो उन्होंने देवि शबरी को ही अपने आश्रम का उत्तराधिकारी बनाया। अर्थात वनवासी समाज में जन्मी स्त्री महर्षि मातंग आश्रम की उत्तराधिकारी बनीं। देवी शबरी ने ऋषि आश्रम में अपना महत्व अपनी सेवा और समर्पण से बनाया था न कि अपने जन्म जाति के आधार पर।

यह कथा भारतीय समाज के बारे में किये जाने वाले उन सभी दुष्प्रचारों का खंडन करती है जिनमें कहा जाता है कि भारत में जन्म और जाति के आधार पर भेदभाव होता था और स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हो सकता है कुछ अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएँ हुईं हों, पर पूरा समाज ऐसा नहीं था। जैसे किसी गाँव में दो-चार चोर रहते हों किंतु उन दो-चार की कहानी को प्रचारित कर पूरे गाँव को बदनाम किया जाए। विदेशी विचारकों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिये ऐसी कूटरचित घटनाओं का उल्लेख किया और समाज को बांटने का षड्यंत्र किया। वह जन मानस में कुछ इस प्रकार बैठा कि बड़ी संख्या में भारतीय जन जन्म और जाति आधार को ही मुख्य मानने लगे। ऐसी तमाम साहित्य रचना मध्यकाल में ही हुई। यदि भारत में वनवासी समाज को हेय समझा जाता या स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता तो न देवी शबरी को ऋषि आश्रम में रहने का स्थान मिलता और न ऋषि आश्रम की उत्तराधिकारी बनतीं। वेदों की ऋषिकाएँ, ऋषि आश्रम की गुरु माताएँ ही नहीं, भारत में शिक्षा प्रमुख कोई देवता नहीं देवी सरस्वती हैं। मातंग ऋषि त्रिकाल दर्शी थे। वे जानते थे कि अयोध्या में भगवान नारायण का अवतार होने वाला है और वे इसी मार्ग से निकलेंगे। महर्षि मातंग ने यह रहस्य भी केवल देवी शबरी को ही बताया था और देवी शबरी भक्ति में डूबकर रामजी की बाट जोहने लगीं। वर्षों तक राह देखी। तब उनकी साध पूरी हुई और जब रामजी आये तो वे विहल हो उठीं। इतनी विहल कि अतिथि सम्मान की सभी औपचारिकता ही भूल गईं। दौड़ कर ताजा बेर तोड़ कर लाईं। कोई खट्टा बेर प्रभु के मुँह का स्वाद न बिगाड़ दे, यह सोचकर एक एक बेर चखकर खिलाने लगीं। रामजी भी भक्ति विभोर होकर जूठे बेर भी स्वाद से खाने लगे।

रामजी देवी शबरी के आश्रम में जाने से पहले महर्षि अत्रि के आश्रम भी गये थे, जहाँ देवी अनुसुइया ने माता सीता को उपदेश किया था। माता अनुसूइया उपदेश करती हैं और देवी शबरी ऋषि आश्रम की प्रमुख हैं। रामायण काल के इन दोनों प्रसंगों में यह स्पष्ट संदेश है कि भारतीय समाज में नारी आश्रम प्रमुख भी रही हैं और उपदेशकर्ता भी हैं। रामायण काल में भील वनवासी समाज में जन्मी देवी शबरी को ही आश्रम और भक्ति में उच्च स्थान नहीं मिला। रामजी ने निषात, किरात, केवट आदि समाज से संबंधित व्यक्तियों को मित्रता का सम्मान दिया था। यह सभी प्रसंग भारतीय समाज के समरस स्वरूप को ही सामने लाते हैं।

शबरी प्रसंग में संकल्प की सार्थकता के लिये एकाग्रता और समर्पण से कार्य करने का संदेश भी मिलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिये एकाग्रता, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। देवी शबरी ने एकाग्रता और समर्पण से गुरु सेवा भी की और रामजी की प्रतीक्षा भी एकाग्रता और समर्पण से की। मातंग ऋषि के आश्रम में जाने के लिये देवी शबरी ने सेवा का मार्ग चुना और उसपर आजन्म पालन किया। गुरु या शिक्षक के प्रवचन या व्याख्यान से तो ज्ञान मिलता ही है। साथ ही समर्पित शिष्य की आत्मशक्ति गुरु या शिक्षक के आत्मिक अनुराग से भी जाग्रत होती है जो उसे अन्य सहपाठियों से विशिष्ट बनाती है।

जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिये समर्पण युक्त कर्म कर्तव्य चाहिये और प्रभु के मन में विशिष्ठ स्थान बनाने के लिये भी भक्ति का समर्पण चाहिये। देवी शबरी ने एकाग्र और समर्पण भाव गुरु सेवा भी की थी और रामजी की राह भी देखी। दिनरात उन्हीं का स्मरण किया। भक्ति के समर्पण की यह पराकाष्ठा किसी अन्य भक्त में नहीं मिलती। यह उनके समर्पण का सम्मोहन ही था कि प्रभु राम उनके जूठे बेरों का भी आनंद लेते रहे। देवी शबरी की यह कथा रामजी के भक्त वत्सल स्वरूप को तो सामने लाती ही है। साथ ही यह संदेश भी देती है कि व्यक्ति को अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति एकाग्रता और समर्पण से कार्य करने से ही होती है। वह सफलता पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हो या प्रभु को प्राप्त करने की हो।

आजकल

गरीबी में कमी, खर्च दोगुने

अर्थव्यवस्था के तेज विकास और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के दावों के बीच हकीकत यह है कि पिछले बारह-तेरह सालों में लोगों का घरेलू खर्च बढ़ कर दोगुने से अधिक हो गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ताजा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत घरेलू खर्च 2011-12 के 2,630 रुपए से बढ़ कर 2022-23 में दोगुने से अधिक यानी 6,459 रुपए हो गया है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में यह 1,430 रुपए से बढ़कर 3,773 रुपए हो गया है।

इसमें यह भी जाहिर हुआ है कि गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है, जबकि खाद्यान्न पर खर्च पहले की तुलना में कम हुआ है। फलों, सब्जियों, दूध, मछली, खाद्य तेल आदि पर खर्च बढ़ा है। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, वस्त्र और दूसरी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है। इसकी एक वजह तो यह बताई जा रही है कि कोविड के समय शहरों से गांवों की तरफ लौटे लोगों के कृषि क्षेत्र में समाहित हो जाने से उस क्षेत्र का औसत उपभोग खर्च बढ़ा है। मगर यही तर्क शहरी खर्च बढ़ने पर लागू नहीं होता। यह तब है, जब सरकार लगातार महंगाई पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। इन आंकड़ों के समांतर दावा यह भी है कि गरीबी में पांच फीसद की कमी आई है। बहुआयामी गरीबी से करीब तेईस करोड़ लोगों के बाहर निकलने का आंकड़ा भी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। इन सबके बीच एक तथ्य यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक आय भी लगभग उतनी ही है, जितना प्रति व्यक्ति मासिक खर्च है। मगर इससे प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति खर्च का समीकरण संतुलित नहीं होता। ज्यादातर परिवारों में एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है, जबकि उस पर निर्भर औसतन तीन लोग होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के बीच सरकार का दावा है कि वह बयासी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। यानी प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय के औसत में इस आबादी का हिस्सा भी शामिल है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि यह सर्वेक्षण ग्यारह सालों बाद आया है, इसलिए इसमें प्रति व्यक्ति खर्च ऊंचे स्तर पर नजर आ रहा है।

पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज

अरुण नैथानी

पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में मुख्यमंत्री बनने वाली मरियम नवाज पहली महिला हैं। वे इसी माह हुए चुनाव में पाक संसद के लिये चुनी गई थीं। उन्हें पाकिस्तान में बेहद विवादित महिला राजनेता के रूप में जाना जाता है। पिछले दिनों पर्दे के पीछे से सेना के गहरे दखल के बीच पाकिस्तान में लोकतंत्र का प्रहसन पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अब राजनीतिक वंशवाद की फसल लहलहा रही है। राजनीति के चतुर खिलाड़ी नवाज शरीफ ने सत्ता के लिये शतरंज की बिसात बिछाई तो मुल्क की बागडोर थामने के लिये थी, लेकिन जनाक्रोश ने तस्वीर बदल दी। जेल के भीतर से भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खेला करने में कामयाब हो गए। तमाम चुनावी धांधलियों के बावजूद राजनीतिक हालात ऐसे बन गए कि नवाज चाहकर भी प्रधानमंत्री न बन सके। फिर उन्होंने जोड़तोड़ करके सत्ता की बागडोर भाई के जरिये हासिल करने की कोशिश की। साथ ही अपने राजनीतिक गढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री रहे शहबाज शरीफ के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद वहां की राजनीति पर भी वर्चस्व बनाये रखना मकसद था। फलत: बड़ी बेटी मरियम को पंजाब सूबे की कमान सौंप दी गई है। पाकिस्तान तहरीके-इंसाफ के मुखर विरोध और बहिष्कार के बीच मरियम नवाज को पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है।

यूं तो मरियम नवाज को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन काफी अर्से तक वे पिता व चाचा के साथ राजनीतिक अभियानों में हिस्सेदार रही हैं। पिता के राजनीतिक अभियानों से पहले दूर रहने वाली मरियम तब सुर्खियों में आई जब उनके पिता का तख्ता पूर्व सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने पलटा था। वर्ष 1999 के दौरान जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कैद में डाल दिया था। तब मरियम अपनी मां के साथ पिता को रिहा कराने के लिये सड़कों पर उतरीं। उन्होंने जनरल मुशर्रफ की सैन्य तानाशाही के खिलाफ जनमत बनाने का प्रयास किया। दरअसल, सैन्य तानाशाह ने शरीफ परिवार के सभी पुरुषों को या तो गिरफ्तार कर लिया था या फिर वे नजरबंद थे। फिर कूटनीतिक प्रयासों से मामले में सऊदी अरब की एंट्री हुई। सऊदी शासक की मदद से नवाज शरीफ व परिवार को अभयदान दिलाया गया। एक समझौते के बाद शरीफ परिवार सऊदी अरब में निर्वासित जीवन जीने लायक बना।

राजनीतिक पंडित बताते हैं कि निर्वासन के दौरान मरियम ने राजनीति का ककहरा सीखा और खुद को पाक के चुनौतीपूर्ण हालात के लिये तैयार करने का प्रयास किया। कालांतर में वर्ष 2007 में शरीफ परिवार की वापसी हो सकी। वैसे मरियम की राजनीतिक सक्रियता की पारी चाचा शहबाज के चुनाव अभियानों में शिरकत करने के साथ शुरू हुई। उन्होंने महिला वोटरों को रिझाने के लिये विभिन्न अभियानों में भाग लिया। एक महिला होने के नाते उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। पढ़ी-लिखी मरियम ने बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया के महत्व को समझा और पार्टी के लिये इस अभियान में गहरी पकड़ बनायी। दरअसल, इमरान खान की पार्टी पीटीआई की लगातार युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिये मरियम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फिर वे पिता द्वारा स्थापित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन के सोशल मीडिया सेल को मजबूत करने में सूत्रधार बनी, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं रही। इस साल हुए विवादित चुनावों में वे नेशनल असेंबली के लिये पहली बार चुनी गईं।

नवाज शरीफ की सबसे बड़ी संतान मरियम नवाज लंबे समय तक चुपचाप अपने दो बच्चों की परवरिश में लगी रही हैं। यूं तो शरीफ परिवार अपनी रुढ़िवादी परंपराओं के लिये जाना जाता है। ऐसे में बेटी के राजनीति में आने की संभावना को लोग कम ही देखते थे। लेकिन राजनीतिक हालात और नवाज व सेना के बीच जारी टकराव ने मरियम के सक्रिय राजनीति में आने के हालात बना दिये। उनका विवाह एक सैनिक अधिकारी से हुआ है। उनके पति नब्बे के दशक में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री काल में एडीसी थे। यूं तो मरियम का आकर्षक व्यक्तित्व पाकिस्तानी अवाम को प्रभावित करता रहा है, लेकिन उनकी गिनती पाकिस्तान के खासे विवादित लोगों में होती है। वे मुखर हैं और अच्छी वक्ता हैं। उनकी पार्टी के लोग मुश्किल वक्त में संगठन का नेतृत्व करने के लिये उनकी प्रशंसा करते हैं। तो दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दल वंशवाद की उपज मरियम को लेकर लगातार आक्रामक रहे हैं। उनका मानना है कि वह शरीफ परिवार के भ्रष्टाचार की पोषक हैं।